नतीजतन, इस संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, अपीलीय न्यायालय के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और अपीलीय न्यायालय को निर्देश अब गुण-दोष के आधार पर अपील सुनने और कानून के अनुसार इसका निपटान करने के लिए आगे बढ़ना है। इस आवेदन में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। पक्षकारों को 20 नवंबर, 1967 को अपीलीय अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

के.एस.के.

सिविल विविध

टेक चंद जे के समक्ष

नेशनल कॉलेज की प्रबंध समिति, - *प्रार्थी*

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, उत्तरदाता

1967 की सिविल रिट संख्या 135

20 अक्टूबर, 1967

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम (1947 का VII) - 2 (सी), 5, 11 (2), 20, 27, 29 और *31(2)*-पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर - अध्याय *III(A) - विनियम* 11 *और* 12 *- सीनेट द्वारा* पारित विनियम *- क्या सिंडिकेट द्वारा संशोधित या संक्षिप्त किया जा सकता है - "विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी"- इसका अर्थ है - एक संबद्ध कॉलेज के स्थायी प्रिंसिपल की सेवाओं की समाप्ति- विश्वविद्यालय की सहमति - यदि आवश्यक हो - सिंडिकेट की शक्ति कि वह किसी संबद्ध कॉलेज को कुछ कार्रवाई करने के लिए बुला सकता है; क्या यह विनियम* 11 *और* 12 *पर अतिक्रमण के समान है - भारत के संविधान* (1950) - *अनुच्छेद* 226 *- प्रशासनिक आदेशों - क्या इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।*

यह माना गया कि पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट को पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 या उसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा सरकार की मंजूरी से सीनेट द्वारा बनाए गए विनियमों में संशोधन करने या उन्हें कम करने की कोई शक्ति नहीं है। वाक्यांश "विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी", को इसके दायरे में उन विनियमों को बनाने या जोड़ने की सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ नहीं दिया

जा सकता है जो केवल सीनेट में निहित हैं और वह भी सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद। सिंडिकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार नहीं है जिसे सख्ती से तथाकथित कहा जाता है, बल्कि मामलों को प्रशासित और प्रबंधित करने और विश्वविद्यालय के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति वाला एक निकाय है।

यह माना गया कि यह व्यवस्था है कि अधिनियम की धारा 27 में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के आवेदन में यह आश्वासन होगा कि कॉलेज संबद्ध होने के बाद प्रबंधन के किसी भी स्थानांतरण और शिक्षण स्टाफ में सभी परिवर्तनों की सूचना सिंडिकेट को तत्काल दी जाएगी। लेकिन इस आवश्यकता के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है ताकि स्थायी प्रिंसिपल की सेवाओं को समाप्त करने से पहले विश्वविद्यालय की उचित सहमति की आवश्यकता वाले सिंडिकेट के निर्णय को प्रस्तुत करना शामिल हो। सिंडिकेट का यह निर्णय, जहां तक यह विनियम की अपेक्षाओं के विपरीत है, अवैध और *अधिकारहीन है।*

यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 29 सिंडिकेट को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह प्रत्येक संबद्ध कॉलेज का निरीक्षण करवाए, और इस प्रकार निरीक्षण किए गए किसी भी कॉलेज को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने के लिए बुला सकता है, जो उन्हें अधिनियम की धारा 27 (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो। हालांकि, धारा 29 की भाषा को इस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसमें विनियम 11 और 12 के दायरे को प्रभावित करने वाली एक नई शर्त को शामिल किया जा सके।

यह माना गया कि रिट या निर्देशों का मुद्दा उच्च न्यायालयों के न्यायिक विवेकाधिकार में है और न्यायालयों द्वारा किसी भी सूत्र के रूप में निर्धारित करना उचित नहीं माना गया है, कि विवेकाधिकार का उपयोग केवल ऐसी परिस्थितियों में किया जाना है। संविधान के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां विशेषाधिकार रिट जारी करने तक ही सीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को "कोई निर्देश, आदेश या रिट" जारी करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय के पास ऐसे प्रशासनिक आदेशों के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है जो कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना में या

किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना किए जाते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, *जिसमें प्रार्थना की गई है कि यह* अनुलग्नक Q में निहित प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अवैध आदेश को रद्द करने के लिए *प्रमाणपत्र, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश की प्रकृति में रिट जारी की जाए।*

एन.एस. ग्रेवाल याचिकाकर्ता की ओर से, वकील।

एच.आर. सोढ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता, एन.के. सोढ़ी और आर.एल. बत्ता, वकील के साथ, उत्तरदाताओं के लिए।

आदेश

टेक चंद, जे- यह नेशनल कॉलेज, सोठियाला, तहसील और जिला अमृतसर की प्रबंध समिति द्वारा रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के खिलाफ महासचिव ब्रिगेडियर जीएस बल के माध्यम से दायर एक याचिका है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* एक रिट या उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता कॉलेज के प्राचार्य श्री करतार सिंह के निलंबन या बर्खास्तगी पर अपनी सहमति वापस लेने के विश्वविद्यालय के निर्णय को पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के *विपरीत* बताते हुए और

अधिकार क्षेत्र के बिना और इसे रद्द करना, और इसके अलावा, विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को कानूनी रूप से बर्खास्त कर्मचारी को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता को अवैध रूप से मजबूर करने से रोकने के लिए निषेध रिट जारी करना।

याचिकाकर्ता ने करतार सिंह को कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया, लेकिन बाद में उन्हें "अपने स्टाफ के सदस्यों और कुछ छात्रों के प्रति घोर लापरवाह, अक्षम, अनुशासनहीन, अधीनस्थ, प्रतिशोधी पाया, जो अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने और अन्यथा बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित होने सहित अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खुद को कदाचार करने के लिए किया गया था"। इसलिए सर्वसम्मति से उन्हें तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने और पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1966 के अध्याय 3 (ए) (1) में विनियम 11 से 14 के तहत उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच करने का निर्णय लिया गया। इस सर्वसम्मत संकल्प के अनुसरण में श्री करतार सिंह को 20 मार्च, 1966 को निलंबित कर दिया गया और 2 अप्रैल, 1966 को अनुलग्नक A के *तहत* उन्हें आरोप-पत्र जारी किया गया और 27 अप्रैल, 1966 को उन्हें एक पूरक आरोप-पत्र जारी किया गया (अनुपत्र B)। श्री करतार सिंह ने अनुपत्र 'A-1' और 'B-1' *के माध्यम से* अपने लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए । याचिकाकर्ता समिति

स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने के कारण, तथ्यों और आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यों की एक उप-समिति नियुक्त की। उत्तर में, श्री करतार सिंह ने दिनांक 10 मई, 1966 (अनुलग्नक 'G') और दिनांक 13 मई, 1966 (अनुलग्नक 'H') के दो पत्र भेजे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। जांच समिति द्वारा उन्हें एक और अवसर दिया गया था जिसमें उन्हें उप-समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन श्री करतार सिंह नहीं आए और उन्होंने समिति को एक पत्र भेजा, जिसकी प्रति अनुपत्र 'K' है। तब यह कहा जाता है कि जांच उप-समिति ने चालीस गवाहों के बयान दर्ज किए और सर्वसम्मति से उन्हें एक को छोड़कर सभी आरोपों का दोषी पाया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की । याचिकाकर्ता समिति ने सर्वसम्मति से उप-समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और श्री करतार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्हें बर्खास्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके लिए उन्हें दो दिन का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने कभी कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया। परिणामस्वरूप, श्री करतार सिंह को 16 जून, 1966 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

58J

1 जनवरी, 1966 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता समिति के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा जिसमें सिंडिकेट के निम्नलिखित निर्णय की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया: -

> "एक संबद्ध कॉलेज में स्थायी प्रिंसिपल की सेवाओं को विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबंध 'N' के माध्यम से, रजिस्ट्रार ने कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव को दिनांक 10 मई, 1966 को उनके पूर्व प्रश्न के उत्तर में एक पत्र लिखा था कि स्थायी प्राचार्य के मामले में, उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले कुलपति की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी थी। उपर्युक्त के अनुपालन में महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव ने श्री करतार सिंह की बर्खास्तगी की परिस्थितियों और अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कुलसचिव को लिखा -

पत्र में कहा गया है, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप

श्री करतार सिंह, एमए, प्रिंसिपल के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रस्तावित कार्रवाई को अपनी मंजूरी दें।

अनुपत्र 'P' के माध्यम से। 8 दिसम्बर, 1966 को आयोजित सिंडिकेट की बैठक में प्रधानाचार्य के निलंबन या बर्खास्तगी को सहमति न देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से याचिकाकर्ता समिति को 29 दिसम्बर, 1966 को पत्र 'Q' द्वारा अवगत करा दिया गया था। यह उल्लेख किया गया था -

नेशनल कॉलेज सठियाला के प्राचार्य एस. करतार सिंह के निलंबन या बर्खास्तगी पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति नहीं देता है और कॉलेज के अधिकारियों से उन्हें तुरंत बहाल करने के लिए कहा जाए।

समिति से श्री करतार सिंह को तत्काल बहाल करने के लिए कहा गया था। और विश्वविद्यालय को तदनुसार सूचित किया जाए- अनुपत्र 'Q' के अनुसार। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि सिंडिकेट ने कॉलेज को असंबद्ध करने की दृष्टि से कार्रवाई करने का निर्णय लिया था और संबद्धता रद्द करने के नोटिस जारी किए गए थे। इन कार्यवाहियों में, कॉलेज को असंबद्ध करने की कार्रवाई रिट याचिका का विषय-वस्तु नहीं बनती है। विवाद विश्वविद्यालय की शक्ति तक ही सीमित है कि वह याचिकाकर्ता को बर्खास्त प्रिंसिपल को बहाल

करने का आदेश दे।

याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों के साथ प्राचार्य की घनिष्ठ मित्रता को देखते हुए उस पर अवैध रूप से दबाव बनाने और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रजिस्ट्रार द्वारा सहायक शिक्षा अधिकारी, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 28 दिसम्बर, 1966 को एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:-

"सिंडिकेट ने फैसला किया:

(१) कॉलेज का निरीक्षण करने, आगे की जांच करने और सिंडिकेट को रिपोर्ट करने के लिए श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रिंसिपल ओ.पी. मोहन और डॉ एस.एस. आनंद की एक समिति नियुक्त की जाए।

(२) नेशनल कॉलेज सठियाला के प्राचार्य एस. करतार सिंह के निलंबन या बर्खास्तगी पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति नहीं देता है और कॉलेज के अधिकारियों से उन्हें तुरंत बहाल करने के लिए कहा जाए।

सिंडिकेट के इस निर्णय के बावजूद, जिसे 14 दिसम्बर,

1966 को कॉलेज के सचिव को विधिवत सूचित कर दिया गया था, उन्होंने अभी तक प्राचार्य श्री करतार सिंह को बहाल नहीं किया है। इन परिस्थितियों में इस महाविद्यालय को स्वीकृत 8,000 रुपये के अनुदान की तीसरी किस्त का भुगतान आपके *दिनांक 19 मई, 1966 के पत्र सं.एफ-15-6 (i)/61-पीई 1* के माध्यम से रोक दिया गया है।

(अनुलग्नक 'R')। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 3 जनवरी, 1967 को याचिकाकर्ता समिति के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें कहा गया था:

"जैसा कि आप जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने श्री करतार सिंह को आपके कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटाने के आपके फैसले से सहमति नहीं दी है, और सिंडिकेट ने आगे निर्णय लिया है कि उन्हें तत्काल बहाल किया जा सकता है - इस प्रकार श्री करतार सिंह आपके कॉलेज के सही प्रिंसिपल हैं। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की गई विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अपने कॉलेज से उपस्थित होने वाले छात्रों के प्रवेश फॉर्म जमा करें।

अनुलग्नक 'S' के अनुसार। याचिकाकर्ता की शिकायत विश्वविद्यालय के 14 दिसंबर, 1966 के आदेश (अनुबंध 'Q') में है जिसमें याचिकाकर्ता को श्री करतार सिंह को तुरंत बहाल करने की आवश्यकता है; यह अधिकार क्षेत्र से परे था, *अधिकार क्षेत्र से परे* था और गुप्त विचार से प्रेरित था और संचार अनुबंध 'R' और 'S' का चरित्र याचिकाकर्ता को डराने और दबाव डालने के उद्देश्य से था कि वह विश्वविद्यालय की अवैध मांगों को प्रस्तुत करे क्योंकि इसके अधिकारी श्री करतार सिंह को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाना चाहते थे। यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले यह आवश्यक करके छात्रों को नुकसान पहुंचाने की हद तक चले गए कि याचिकाकर्ता के कॉलेज से विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों के प्रवेश फॉर्म को श्री करतार सिंह द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए, हालांकि उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। रजिस्ट्रार द्वारा याचिकाकर्ता समिति के सचिव को 9 जनवरी, 1967 को भेजे गए एक अन्य पत्र (अनुलग्नक T) का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया था:

> पत्र में कहा गया है, 'मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कुलपति ने आदेश पारित किया है कि नेशनल कॉलेज, सठियाला के अनुमोदित प्राचार्य करतार सिंह

को छोड़कर किसी अन्य प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित विश्वविद्यालय के व्यवसाय आदि से संबंधित कोई भी कागजात इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे.'

इससे संतुष्ट नहीं होने पर विश्वविद्यालय ने कॉलेज में प्रवेश फॉर्म वापस कर दिए ताकि नेशनल कॉलेज, सठियाला के प्रिंसीपल एस करतार सिंह से इन्हें सत्यापित किया जा सके और अनुपालन के बाद इस कार्यालय में फिर से जमा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि उस तारीख तक न केवल श्री करतार सिंह ने प्राचार्य पद छोड़ दिया था, बल्कि एक अन्य प्राचार्य की नियुक्ति भी कर दी गई थी। इस उदाहरण को याचिकाकर्ता के प्रति प्रतिशोधी रवैये के उदाहरण *के रूप में उद्धृत किया गया था और* बर्खास्त प्रिंसिपल श्री करतार सिंह के खिलाफ घोर पक्षपात के कार्य के रूप में उद्धृत किया गया था। याचिकाकर्ता को उसे बहाल करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से इन सभी उपायों का सहारा लिया गया था।

विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल विवरणी में इस बात की जानकारी नहीं होने की दलील दी गई है कि श्री करतार सिंह के कर्मचारियों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, अवज्ञा या प्रतिशोध आदि के दोषी होने के आरोप कहां तक सही हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति

के बिना किसी संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य की बर्खास्तगी का आदेश नहीं दिया जा सकता है। *दुर्भावना* के आरोप *से* इनकार किया गया। याचिकाकर्ता कॉलेज ऑफ एफिलिएशन को दिए गए नोटिस का भी संदर्भ दिया गया था। कुलपति की पूर्व सहमति के अनुसार, यह दावा किया गया था कि यह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार था, हालांकि वास्तविक नियम का हवाला नहीं दिया गया था। अनुपत्र R-2 के माध्यम से सिंडिकेट के एक निर्णय का उल्लेख किया गया था। बर्खास्त प्रिंसिपल को बहाल किए जाने तक सहमति देने से इनकार करने के आरोप से इनकार नहीं किया गया था।

इस मामले में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के पास यह निर्णय लेने की शक्ति थी कि किसी संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य की बर्खास्तगी से पहले, विश्वविद्यालय के कुलपति की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी थी, और क्या इस तरह के निर्णय में याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नियम का बल था। इस स्तर पर विश्वविद्यालय अधिनियम और विनियमों का संदर्भ आवश्यक है। पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 (c) "विनियमन" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "सीनेट द्वारा किया गया कोई भी विनियमन"। धारा 11 (2) के तहत सीनेट के पास "विश्वविद्यालय के मामलों, चिंताओं और संपत्ति का पूरा प्रबंधन

और अधीक्षण है और उस प्रबंधन के लिए प्रावधान करेगा, और उस अधीक्षण को कुछ समय के लिए लागू विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार प्रयोग करेगा"। सिंडिकेट का उल्लेख करते हुए धारा 20 में प्रावधान है कि "विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी....."। धारा 31 विनियमों से संबंधित है और यह प्रावधान करती है कि सरकार की मंजूरी से सीनेट समय-समय पर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकती है। उप-धारा (2) में मदों (क) से (उ) को विशिष्ट किया गया है, अंतिम मद विनियम है जिसमें विश्श्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी कॉलेजों के अलावा अन्य महाविद्यालयों के समुचित प्रशासन के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है।

गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने के लिए विनियम पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय III (ए) में निहित हैं। इस मामले में, संबंधित विनियम 11 और 12 हैं जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "11. विनियम संख्या 12, 13, 14 और 15 में निहित बातों के अधीन रहते हुए, गैर-सरकारी कॉलेज का शासी निकाय किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति का निर्धारण करने का हकदार होगा, जो उसे तीन महीने

का नोटिस लिखित में देने या नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान करने के बाद होगा एक अच्छे कारण के लिए, बशर्ते कि नैतिक अधमता या कदाचार के मामले में शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार होगा। निलंबन की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी जिसके भीतर मामले का फैसला किया जाना चाहिए। निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को कर्मचारी के वेतन की आधी राशि के बराबर भत्ता दिया जाएगा। यदि अंततः कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है, तो इस तरह के निष्कासन के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी और न ही इसके बदले में कोई वेतन दिया जाएगा।

12. शासी निकाय किसी कर्मचारी की नियुक्ति का निर्धारण नहीं करेगा, चाहे सरसरी तौर पर या अन्यथा, उसे उन आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित किए बिना, जिन पर वे कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं और उसे लिखित रूप में अपना मामला बताने का उचित अवसर दिए बिना; और अंतिम निर्णय पर आने से पहले, शिक्षक के कथन पर विधिवत विचार करेगा और यदि वह चाहता है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई देगा।

विश्वविद्यालय की ओर से यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा इन दो विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था, न ही यह तर्क दिया गया है कि इन दोनों के अलावा अन्य विनियम हैं जिनके अनुपालन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय का मामला यह है कि सिंडिकेट ने 23 सितम्बर, 1961 को अपने द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया था जो निम्नानुसार है -

> "संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में पहले से निर्धारित सेवा शर्तों के अलावा, प्रिंसिपलों के लिए निम्नलिखित दो शर्तें भी जोड़ी जाएं: -
>
> (१) किसी संबद्ध कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति से पहले, विश्वविद्यालय का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए;
>
> (२) विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति के बिना संबद्ध कॉलेज में स्थायी प्रिंसिपल की सेवा समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

R -2 के अनुसार।

प्रश्न यह उठता है कि क्या सिंडिकेट के लिए ऐसा निर्णय लेना खुला है जो ऊपर पुनरुत्पादित विनियम 11 और 12 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। किसी गैर-सरकारी कॉलेज की

सेवा में किसी कर्मचारी को निलंबित या बर्खास्त करने की शक्ति जिसका अर्थ है कि प्रिंसिपल सहित एक शिक्षक को ऐसे कॉलेज के शासी निकाय में मान्यता दी गई है और ऐसा करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रिया के अनुपालन में, शासी निकाय "एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति का निर्धारण करने का हकदार होगा"। नोटिस करने और अवसर देने के संबंध में सामान्य सुरक्षोपाय विनियमों में निर्धारित किए गए हैं और इस मामले में उनका पालन किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शासी निकाय की यह शक्ति, जो केवल सीनेट द्वारा और सरकार की मंजूरी से बनाई जा सकती है, सिंडिकेट के संकल्प द्वारा कम की जा सकती है या संशोधित की जा सकती है। सिंडिकेट के पास अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है। विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा अधिनियम की धारा 20 का संदर्भ दिया गया था, कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना या सिंडिकेट द्वारा उन्हें जोड़ना विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार का अभ्यास माना जा सकता है। मुझे यह सोचना चाहिए था कि "कार्यकारी सरकार" शब्द का उपयोग करना "सरकार" शब्द की तुलना में अधिक उपयुक्त होगा। उत्तरार्द्ध अभिव्यक्ति "सरकार" कुछ अस्पष्टता को स्वीकार

करती है, क्योंकि इसका अर्थ न केवल शासन की कार्रवाई या तरीके से है, जो वास्तव में "सरकार" शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, बल्कि सरकार का कार्यालय या शासन करने का अधिकार भी है। सिंडिकेट कार्यकारी सरकार नहीं है जिसे सख्ती से तथाकथित कहा जाता है, बल्कि मामलों को प्रशासित और प्रबंधित करने और विश्वविद्यालय के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति वाला एक निकाय है।

यहां तक कि वाक्यांश "विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी", को विद्वान वकील द्वारा विनियमों को बनाने या जोड़ने की सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जो केवल सीनेट में निहित हैं और वह भी सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, सीनेट के निर्णय के माध्यम से विनियम 11 और 12 को कम करने या संशोधित करने की शक्ति इस अधिनियम की धारा 20 द्वारा प्रदत्त नहीं माना जा सकता है। इसी संबंध में धारा 27 का भी संदर्भ दिया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय से कॉलेज की संबद्धता के लिए आवेदन में एक आश्वासन होगा कि कॉलेज संबद्ध होने के बाद, प्रबंधन के किसी भी हस्तांतरण और शिक्षण कर्मचारियों में सभी परिवर्तनों को तुरंत

सिंडिकेट को सूचित किया जाएगा। किसी मामले को सिंडिकेट के ध्यान में लाने का मतलब यह नहीं है कि सिंडिकेट के पास विनियमों में निर्धारित चीजों को जोड़ने या बदलने की शक्ति है। इस मामले में, यह विश्वविद्यालय की शिकायत नहीं है कि संबद्धता के लिए आवेदन में विशिष्ट आश्वासन शामिल नहीं था और कर्मचारियों में परिवर्तन की सूचना नहीं दी गई थी। इस आवश्यकता के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है ताकि स्थायी प्रिंसिपल की सेवाओं को समाप्त करने से पहले विश्वविद्यालय की उचित सहमति की आवश्यकता वाले सिंडिकेट के निर्णय को प्रस्तुत करना शामिल हो। सिंडिकेट का यह निर्णय, जहां तक यह विनियम की अपेक्षाओं के विपरीत है, अवैध और अधिकारहीन है। विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने धारा 29 के प्रावधानों के तहत सिंडिकेट के फैसले को सही ठहराने की मांग की, जिसमें एक संबद्ध कॉलेज को रिपोर्ट, रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि सिंडिकेट की आवश्यकता हो सकती है और यह भी कि सिंडिकेट ऐसे प्रत्येक कॉलेज का निरीक्षण करेगा। सिंडिकेट को यह शक्ति देते हुए कि वह इस प्रकार निरीक्षण किए गए किसी कॉलेज को एक विनिदष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने के लिए कह सकता है, जो धारा 27(1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उन्हें आवश्यक प्रतीत हो, मुझे नहीं लगता कि धारा 29 से कोई मदद मिलती

है; और भाषा को इस तरह से नहीं खींचा जा सकता है कि इसमें विनियम 11 और 12 के दायरे को प्रभावित करने वाली एक नई शर्त को शामिल किया जा सके।

विद्वान वकील का अंतिम उपाय धारा 5 के प्रावधानों से संबंधित था, जो शिक्षा प्रदान करने, सीखने की उन्नति, मूल अनुसंधान के अभियोजन, शिक्षकों को नियुक्त करने, शैक्षिक बंदोबस्ती रखने और प्रबंधित करने आदि की शक्ति के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित थे, और "ऐसे सभी कार्य करने के लिए जो अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं"। धारा 5 की भाषा को इस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसमें न केवल धारा 31 (1) के साथ सह-व्यापक शक्ति शामिल हो, बल्कि इससे आगे भी बढ़े। अंत में यह आग्रह किया गया कि सिंडिकेट के कृत्य की शिकायत प्रशासनिक प्रकृति की थी, और ऐसा नहीं था, जिससे याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत उपाय प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। जहां तक विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-सरकारी संस्थाओं का संबंध है, इस प्रश्न में निश्चित रूप से लोक महत्व का मामला शामिल है। रिट या निदेशों का मुद्दा इस न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार में है, और न्यायालयों द्वारा किसी सूत्र के रूप में यह निर्धारित करना उचित नहीं समझा गया है कि विवेकाधिकार का प्रयोग इस प्रकार किया जाना है।

केवल परिस्थितियां। संविधान के तहत न्यायालयों की शक्तियां विशेषाधिकार रिट जारी करने तक ही सीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 226 इस न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को "कोई निर्देश, आदेश या रिट" जारी करने का अधिकार देता है। इस न्यायालय के पास ऐसे प्रशासनिक आदेशों के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है जो कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना में या किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना किए गए हैं। इस मामले में, सिंडिकेट का विवादित निर्णय उन शक्तियों का उल्लंघन था जो सीनेट और सरकार को क़ानून और वैधानिक विनियमों के तहत निहित हैं।

याचिका सफल होने के योग्य है और इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है। इसलिए, मैं विश्वविद्यालय के उस निर्णय को रद्द कर दूंगा जिसमें श्री करतार सिंह, प्रिंसिपल के निलंबन या बर्खास्तगी पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया गया था और आगे याचिकाकर्ता को उन्हें बहाल करने की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय को यह अपेक्षा करने से रोक दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को अपनी सेवा में प्रिंसिपल को वापस लेने की आवश्यकता है, जिसे विनियम 11 और 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया है। विनियम 11 और 12 के अनुपालन के संबंध में इस मामले में की गई किसी भी टिप्पणी को याचिकाकर्ता और प्रिंसिपल

श्री करतार सिंह, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, के बीच विवाद का निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मतभेदों, यदि कोई हों, के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं है। मैंने उन्हें एक ऐसे विवाद में पक्षकार बनने के लिए उचित पक्ष नहीं माना है जो सीधे याचिकाकर्ता और विश्वविद्यालय के बीच है, जिसमें सिंडिकेट द्वारा शक्तियों का प्रयोग अधिकार क्षेत्र की कमी और अवैधता के आधार पर लागू किया गया है। मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

के.एस.के.

रिविजनल सिविल

Before Prem Chand Pandit, J

भगत पंजू राम और अन्य, *याचिकाकर्ता*

बनाम

रैम लाल, - *उत्तरदाता*

1966 का सिविल संशोधन संख्या 4

23 > अक्टूबर 1967 को

*पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (*1949 का III) - *धारा* 8 - दो *बार भुगतान किए गए किराए की वसूली के लिए मुकदमा - चाहे एस द्वारा कवर किया गया हो।* 8.